भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1688

उत्तर देने की तारीखः 27.1**2**.201**8**

विद्यार्थियों के लिए साइकिलें

1688. श्री मानस रंजन भूनियाः

**क्या** मानव संसाधन विकास मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार की कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के स्कूल के विद्यार्थियों को साइकिल देने की कोई योजना है; और**

**(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में विद्यार्थियों को प्रदान की गई**

**साइकिलों की वर्ष-वार तथा राज्य-वार संख्या कितनी है**?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)

**(क) और (ख): जी, नहीं। स्‍कूल शिक्षा हेतु एकीकृत योजना-समग्र शिक्षा (एसएस) को पूरे देश में वर्ष 2018-19 से केंद्र-प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में तीन पूर्व केंद्र प्रायोजित योजनाओं-सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और अध्‍यापक शिक्षा (टीई) का विलय किया गया है। यह स्‍कूल-पूर्व से कक्षा-**XII **तक विस्‍तारित स्‍कूल शिक्षा क्षेत्र हेतु व्‍यापक कार्यक्रम है और इसका लक्ष्‍य स्‍कूल शिक्षा के सभी स्‍तरों पर समावेशी और समान गुणवत्‍ता वाली शिक्षा सुनिश्‍चित करना है। शिक्षा क्षेत्र में सर्वसुलभ पहुंच तथा रिटेंशन, जेन्‍डर तथा सामाजिक वर्ग के अंतरालों को पाटने और स्‍कूल शिक्षा के सभी स्‍तरों पर बच्‍चों के अधिगम स्‍तर में वृद्धि करने के लिए कार्यक्रम के रूप में समग्र शिक्षा को कार्यान्‍वित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है।**

**समग्र शिक्षा कार्यक्रम में कम आबादी वाले, पहाड़ी/घने वन/रेगिस्‍तानी इलाकों तथा शहरी क्षेत्रों जहां भूमि की अनुपलब्‍धता के कारण राज्‍य के** “**आस-पड़ोस**” **के मानदंडों के अनुसार स्‍कूल स्‍थापित करना व्‍यवहार्य नहीं है, वहां परिवहन/एस्‍कोर्ट सुविधा के जरिए प्रारंभिक स्‍कूलों तक बच्‍चों की पहुंच की भी व्यवस्‍था है। परिवहन/एस्‍कार्ट सुविधा के अन्‍तर्गत कक्षा** VIII **तक प्रतिवर्ष प्रति बालक 6000/- रूपए की औसत लागत पर वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है।**

**\*\*\*\*\***